

ન્યાયાલય ઉપ જિલાધિકારી / સહાયક કલેક્ટર (પ્રથમ શ્રેણી) ગાજિયાબાદ

Page 34 of 43 / 2012-13

अन्तर्गत धारा 143 उप्रोजेशन

明治文庫

प्रसादा लालामार्ग

ताहसील व जिला गाजियाबाद

३०८

五

उत्तर प्रदेश सरकार

विकास निर्णय १०-१८-१२

३५ इन्हें प्रस्तुत वाद की कर्यवाही श्रीमति कैला देवी पली स्व. श्री जहाँगीर निवासी ग्राम मारठा परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03-09-2012 जो उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र को माध्यम से अनुरोध किया है कि वादी द्वारा रिक्त नारठा परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता नम्बर 141 खसरा नम्बर 1023 को 0.7575 हेक्टेयर खाता संख्या 139 खसरा नम्बर 1015 रकवा 2.898 हेक्टेयर खसरा नम्बर 1111 रकवा 1.2360 हेक्टेयर को मालिक काबिज संकमणीय भूमिधर के रूप में वादी का नाम देना है। वर्णित खसरा नम्बर की भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त खसरा नम्बर से सम्बन्धित खातीनी वर्ष 1418 ता 14123 की सत्यप्रति दाखिल की गयी है।

यादी का प्रार्थना पत्र जोधु छेतु तहसीलदार गाजियाबाद को भेजा गया, के परिप्रेक्ष्य जिस नायब तहसीलदार (मु) गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05-09-2012 को तहसीलदार गाजियाबाद के समस्त प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 05-09-2012 को अपनी संस्तुति द्वारा उल्लिख आख्या जो उठप्र०ज०विं० एवं भू०व्य० अधिकी की धारा 143 के साथ पठित नियम 135 में विहित प्रारूप दिनांकित 05-09-2012 सहित प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें उद्धरत किया है कि खाता-नी नंपे 1418 ता 1423 फसली के खाता नम्बर 139 खासरा नम्बर 1015 रकमा 2.8920 हैवटेयर खाता नंपे 141 खासरा नम्बर 1023 रकमा 0.7575 हैवटेयर राजस्व अभिलेखों में यादी के नाम अकिल रहण्या 141 खासरा नम्बर 1023 रकमा 0.7575 हैवटेयर राजस्व अभिलेखों में यादी के नाम अकिल है। योगे पर माउजूदीबाल 1 बड़ा कमरा बना हुआ है तथा चार कमरे निर्माणीन है। वर्जित १ मि. की पक्की अकृषिक हो गयी है। प्रस्तुत आख्या को तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 05-09-2012 में वर्जित भूमि की अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है के आधार पर वाद योजित किया गया।

यादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान नामिका वकील राजस्व को सुना गया तथा पत्रायती का आशयन एवं परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सदर्भित भूमि खुर्से की भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए सदर्भित भूमि को उठाप्र०जा०विठ० एवं भूत्या०जाधिठ० की धारा-143 के तहत अकृषिक घोषित किया जाना उचित है। परन्तु स्थानीय विकास प्रधिकारण / निकाय को प्राविधान बाधक न हो, इस हेतु सदर्भित भूमि को किसी भी प्रकार का विकास व निर्माण तथा भू-उपयोग परिवर्तन करने से पूर्व दिवास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय से पूर्व अनुहा प्राप्त करना आवश्यक है।

प्राधिकरण अधिकारी स्वामय निवास से दूर-मुक्ति का लाभ उत्तर प्रदेश अनुमांग-5 लखनऊ संख्या 8164/5-49 ए/03 दिनोंक
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुमांग-5 लखनऊ संख्या 8164/5-49 ए/03 दिनोंक
28-01-2004 मे यह व्यवस्था थी गयी है कि कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित होने पर
उप-जिलाधिकारी द्वारा अभियान चलाकर स्वप्रेरणा से धारा 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी
प्रत्यनगत आराजी गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है। माल अभिलेखों मे कृषि दर्ज होने के
कारण स्वामय अपवाहना हो रही है।

FOR NILAYA INFRA PVT. LTD.
FOR NILAYA INFRA PVT. LTD.

Kulvin Dhillon
Director
Authorised Signatory

(2)

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 लखनऊ संख्या 6416/जी-5-22ए/07 दिनांक 2-8-2007 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि संकमणीय भूमिघर वाला भूमिघर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानीकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संबंधन तथा युक्ति पालन भी है से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगने को इचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जॉच कर प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कि धारा 145 में प्राविधान है कि धारा 143 के प्रख्यापन की एक प्रतिलिपि सब रजिस्ट्रार को भेजी जाय जिससे वह इपिडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में किसी बात के रहते हुए भी उसे बिना शुल्क और नियत रीति से नियन्त्रित कर लेगा। निर्देशित किया गया है कि प्रख्यापन कर स्टाम्प के रूप में राजस्व का अपवर्द्धन रोका जाय। अतः शासनादेशों के अनुपालन में इसे गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक के कार्यवृत्त संख्या 15286 दिनांक 25-09-2007 के पैरा 4 में निर्देश दिये हैं कि जनपद के नगर निकाय सीमा से लगे क्षेत्रों में हो रहे शाहरीकरण को दृष्टिगत विल्डर्स आदि द्वारा कय की जा रही भूमि को सर्वे कराते हुए उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आदादी घोषित करने की कार्यवाही अभियान चलाकर पूर्ण किया जाय।

उक्त तथ्य के दृष्टिगत न्यायालय का मत है कि संदर्भित भूमि को इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा रथानीय निकाय के विकास निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) संबंधी प्राविधान पूर्व की भाँति यथावत लागू रहेगे। यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा 132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति की भूमि को बिना अनुमति कय/विकय करने की नियत से धारा 143 उ०प्र०ज०वि०अ० का प्रख्यापन कराया जा रहा है, तो उस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शासनादेशों के अनुपालन एवं स्टाम्प के अपवर्द्धन से राजस्व की क्षति को रोकने के लिए उ०प्र०ज०वि० एवं भ०व्य०अ० वि० की धारा 143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना आवृद्ध एवं न्यायोचित है।

जनकल आदेश १०-१०-१०

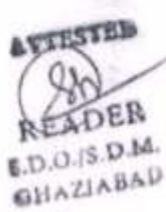
अतः ग्राम मोरटा परगना जलालाबाद के खाता खातीनी वर्ष 1418 सा 1423 फसली वे खाता नम्बर 139 खासरा नम्बर 1015 रक्कवा 2.8920 हैकेटर खाता संख्या 141 खासरा नम्बर 1023 रक्कवा 0.7575 हैकेटर लगानी फर्द फार्डफाटनुसार स्थित ग्राम मोरटा परगना परगना जलालाबाद के तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या शासनादेशों के कम में स्टाम्प अपवर्द्धन रोकने की उदारत्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा रथानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) संबंधी प्राविधान पूर्व की भाँति यथावत लागू रहेंगे, अकृषिक घोषित किया जाता है। यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा 132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है, या वर्णित भूमि अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति की भूमि है, और बिना अनुमति कय/विकय करने की नियत से धारा 143 उ०प्र०ज०वि०अ० का प्रख्यापन कराया जा रहा है, तो उस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यादी को निर्देशित किया जाता है, कि वह कोई भी निर्माण कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त करेगा तथा भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षार कार्यवाही शहरग प्राधिकारी के समक्ष करेगा। आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार गाजियाबाद को अभिलेखों में

For NILAYA INFRA PVT LTD.
Authorised Signatory
[Signature]

(3)

अकित किये जाने हेतु भेजी जाये एवं इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति उप निवन्धक गाजियाबाद को उ०प्र०ज०यि० एवं भ०य्य०अधि० की घारा 143 संपर्कित नियम 137 में अपेक्षा के अनुरूप इण्डियन रेजिस्टरेशन एकट 1908 के तहत निर्बंधन हेतु इस आशय से भेजी जाय कि अपना अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद कि यथावत निर्बन्धित (दैनिक रजिस्ट्रर) में कर दिया गया है, अपने हस्ताक्षर सहित इस न्यायालय को लौटा दें। इस न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक:-10-10-2012



✓/10.10.12
 (केशव कुमार)
 उपजिलाधिकारी
 सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
 गाजियाबाद।

आज यह आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित दर
 न्यायालय की मुद्रा सहित उद्घोषित किया गया।

दिनांक:-10-10-2012



✓/10.10.12
 (केशव कुमार)
 उपजिलाधिकारी
 सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
 गाजियाबाद।

FORNILAYA INFRA PVT. LTD.

Director
 Authorised Signatory

केवल संखारी छप हेतु

पृष्ठा ५ ४१८

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद

वाद संख्या ५५/२०१२-१३

ग्राम मोरटा

विजय सिंह

परगना जलालाबाद

बनाम

अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०ज०वि०अ०

तहसील व जिला गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश सरकार

नामकरण निर्णय । ०।।०।।२०१२-०९-०५

ग्रामपालिका प्रस्तुत वाद की कार्यवाही विजय सिंह पुत्र श्री रामलाल निवासी ग्राम मोरटा परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक ०३-०९-२०१२ जो उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १४३ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि वादी द्वारा रित्त मोरटा परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता नम्बर ९७ खसरा नम्बर १०२३ रकवा ०.३७८७ हैवटेयर खाता ८४७ खसरा नम्बर १०९६ रकवा ०.९६८५ हैवटेयर के मालिक काविज संकरणीय भूमिघर के रूप में वादी का नाम दर्ज है। वर्णित खसरा नम्बर की भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त खसरा नम्बर से सम्बन्धित खतौनी वर्ष १४१८ ता १४२३ की सत्यप्रति दाखिल की गयी है।

वादी का प्रार्थना पत्र जॉच हेतु तहसीलदार गाजियाबाद को भेजा गया, के परिप्रेक्ष्य जॉच नाय तहसीलदार (मु०) गाजियाबाद द्वारा दिनांक ०५-०९-२०१२ को तहसीलदार गाजियाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक ०५-०९-२०१२ को अपनी संस्तुति द्वारा जॉच आख्या जो उ०प्र०ज०वि० एवं भू०व्य० अधि० की धारा १४३ के साथ पठित नियम १३५ में विहित प्रारूप दिनांकित ०५-०९-२०१२ सहित प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें उल्लिखित किया है कि खतौनी वर्ष १४१८ ता १४२३ फसली के खाता नम्बर ९७ खसरा नम्बर १०२३ रकवा ०.३७८७ हैवटेयर खतौनी वर्ष १४१८ ता १४२३ फसली के खाता नम्बर ८४७ खसरा नम्बर १०९६ रकवा ०.९६८५ हैवटेयर राजन्य अभिलेखों में वादी के नाम अंकित हैं। मौके पर वर्णित भूमि की प्रकृति परिवर्तित होकर अकृषिक हो गयी है। प्रस्तुत आख्या को तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक ०५-०९-२०१२ न वर्णित भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है, के आधार पर वाद योजित किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान नामिका वकील राजस्व को सुना गया तथा पत्रावली का अध्ययन एवं परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि संदर्भित भूमि खसरे की भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए संदर्भित भूमि को उ०प्र०ज०वि० एवं भू०व्य०अधि० की धारा-१४३ के तहत अकृषिक घोषित किया जाना उचित है। परन्तु स्थानीय विकास प्रधिकरण / निकाय के प्राविधान बाधक न हो, इस हेतु संदर्भित भूमि के किसी भी प्रकार का विकास व निर्माण तथा भू-उपयोग परिवर्तन करने से पूर्व विकास प्रधिकरण अथवा स्थानीय निकाय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग-५ लखनऊ संख्या ८१६४/५-४९ ए/०३ दिनांक २८-०१-२००४ में यह व्यवस्था दी गयी है कि कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित होने पर २-८-२००७ के द्वारा निर्देशित किया गया है-कि संकरणीय भूमिघर वाला भूमिघर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानीकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुकुरी

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग-५ लखनऊ संख्या ६४१६/जी-५-२२६/०७ दिनांक २-८-२००७ के द्वारा निर्देशित किया गया है-कि संकरणीय भूमिघर वाला भूमिघर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानीकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुकुरी

For NILAYA INFRA PVT LTD
For NILAYA INFRA PVT LTD.

Director
Authorised Signatory

✓



जाति भी है से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है, तो परगने को इंवाज असिस्टेंट कार्डिनल स्वयंसेव अथवा प्रार्थना पत्र पर जाँच कर प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रांत जनीवारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कि धारा 145 में प्राविधान है कि धारा 143 के प्रख्यापन की एक प्रतिलिपि सब रजिस्ट्रार को भेजी जाय जिससे वह इण्डियन रजिस्ट्रार एवं 1908 में चिनी बात के रहने हुए भी उसे दिना शुल्क और नियत रीति से नियमित कर सकता। निवैशिल किया गया है कि प्रख्यापन कर स्टाम्प के ऊपर में राजसव का अपवर्णन रेका लाय जाए। शुसनादेशो के अनुपालन में इसे गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अनपद इतार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा थेटक के कार्यवृत्त खात्या 15266 दिनांक 06.09.2007 के पैरा 4 में निर्देश दिये हैं कि जनपद के गार निकाय सीमा से लगे क्षेत्रों में ही शुसनादेशो को इण्डियन विल्डर्स आदि द्वारा कृष की जा रही भूमि का सर्व कराते हुए उत्तर देश जनीवारी उन्मूलन एवं विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आवादी घोषित करने का निर्देश ही अभियान चलाकर पूर्ण किया जाय।

उक्त तथ्य के वृष्टिगत न्यायालय का सता है कि सदभित भूमि को इस प्रतिवर्त्त के समान विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अनुपालन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) सरकार द्वारा एवं पूर्व की भाति यथायत लागू रहेंगे। यदि प्रस्तुत भूमि के क्षय धारा 132 में घोषित अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की भूमि या विकास अधिनियम 143 / विक्रय करने की नियत से धारा 143 उठप्र०ज०वि०अ० का प्रख्यापन कराया जा रहा है तो उस पर इस आदेश को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुसनादेशो के अनुपालन एवं स्टाम्प के अन्तर्गत साजस्व की क्षति को रोकने के लिए उठप्र०ज०वि० एवं भू०व्य०वि० की धारा 143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किया जाना अभीष्ट एवं व्याप्रोचित है।

लग्नल यादेश ।०-।०-।२-

आत् ग्राम मोरटा परगना जलालाबाद के खाता खतोनी वर्ष 1412 ता 1417 फसली के खाता नंबर 97 खसरा नम्बर 1023 रक्कड़ा 0.3787 हेक्टेयर खतोनी वर्ष 1418 ता 1423 फसली खाता नंबर 347 खसरा नम्बर 1096 रक्कड़ा 0.9685 हेक्टेयर लगानी फर्द फारम्फाटनुसाम नियत पायम भूमि परगना परगना जलालाबाद को लहसीलदार गांजियाबाद की आख्या शासनादेशो के क्षम संघर्ष अपवर्णन रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिवर्त्त के साथ कि विकास प्राधिकरण अभियान विकास एवं निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अनुपालन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) सरकारी प्राविधान पूर्व की भाति अन्य सार्वजनिक भूमि के क्षय धारा 132 में घोषित लागू होगा, अकृषिक घोषित किया जाता है। यदि प्रस्तुत भूमि के विकास अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या घोषित भूमि अनुसूचित जाति/जन जाति की भूमि है और दिना अनुसित कृष / विक्रय करने की नियम से धारा 143 उठप्र०ज०वि०अ० का प्रख्यापन कराया जा रहा है तो उस पर इस आदेश को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाली को नियमित दिया जाता है कि विकास एवं उस पर इस आदेश को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाली को नियमित कराया जाता है कि विकास प्राधिकारी को अनुसित के उपरान्त विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण/समाज प्राधिकारी को अनुसित के उपरान्त विकास प्राधिकरण के समान कराया जाता है। अन्य तथा भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षार कार्यवाही समान प्राधिकारण में समान कराया जाता है। ये प्रतिलिपि लहसीलदार गांजियाबाद को अभिलेखों में अंकित किये जाने हेतु भेजी जाय।

(3)

एवं इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति उप निबन्धक गाजियाबाद को उप्रोजोवि० एवं भूव्य०अधि० की धारा 143 संपर्कित नियम 137 में अपेक्षा के अनुरूप इण्डियन रजिस्ट्रेशन एकट 1908 के तहत निवन्धन हेतु इस आशय से भेजी जाय कि अपना अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद कि यथावत निवन्धित (दैनिक रजिस्ट्रर) मे कर दिया गया है, अपने हस्ताक्षर सहित इस न्यायालय को लौटा दें। इस न्यायालय की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभिलेखागार मे संधित हो।

दिनांक:- 10-10-2012

ARRESTED

~~READER~~
S.D.O./S.D.M.
GHAZIABAD

✓ 10-10-12
(केशव कुमार)

उपजिलाधिकारी
सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
गाजियाबाद।

आज यह आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित लूप
न्यायालय की मुद्रा सहित उद्घोषित किया गया।

दिनांक:- 10-10-2012



✓ 10-10-12
(केशव कुमार)
उपजिलाधिकारी
सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
गाजियाबाद।

For NILAYA INFRA PVT LTD
For NILAYA INFRA PVT LTD
Mukesh Mehta
Director
Authorised Signatory